संख्या:167 / 2015 / 488 / 35-4-2015

प्रेषक ,

अबरार अहमद
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

जिलाधिकारी
बहराइच

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक:29 मार्च,2015

विषय: वर्ष 2014-15 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऊर्जा विभाग की संस्तुति पर जनपद बहराइच के **बहराइच शहर की विद्युत व्यवस्था को भूमिगत किये जाने से सम्बधित परियोजना** को लागत रू. 11130.00 लाख पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, प्रथम किश्त के रूप में रू. 1944.64 लाख (रूपये उन्नीस करोड चव्वालीस लाख चौसठ हजार मात्र) निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की, श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इस कार्य के लिए कार्यदायी संस्था मध्यान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड होगी:-

1- स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।

2- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।

3- निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण उपरांत वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी। विस्तृत आगणन यदि अनुमोदित मूल आगणन से उल्लेखनीय रूप से भिन्न (Significantly different) होते हैं, तो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वास्तविक लागत को शासन स्तर से अनुमोदित कराया जाना अपेक्षित होगा। इस प्रकार अनुमोदित विस्तृत आगणन की प्रति कार्य स्थल के विवरण इत्यादि सहित नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

4- प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप / यथा संशोधित/ स्वीकृत आगणन (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार किये जायेंगे।

5- परियोजना का कार्य स्थानीय स्तर पर विस्तृत सर्वेक्षण के उपरान्त डी.पी.आर. तैयार कर तथा सक्ष्म स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही प्रारम्भ किया जायेगा।

6- जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणन के अनुसार उक्त कार्य हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

7- विद्युत लाईन में जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन है, उनकी सीमा तक नये मीटर का क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों का पूर्ण अनुपालन करते हुये किया जायेगा और यदि नये उपभोक्ताओं को मीटर दिये जाने होगें तो उस पर आने वाले व्यय को मध्यान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा वहन किया जायेगा।

8- प्रश्नगत परियोजना के कार्यान्वयन में सम्भावित डिस्मेन्टलिंग के फलस्वरूप उपलब्ध होने वाली सामग्री का जिलाधिकारी के माध्यम से मध्यान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से मूल्यांकन कराने के बाद मूल्याकित धनराशि राज्य के खाते में जमा की जायेगी।

9- प्रश्नगत परियोजना में आवर हेड चार्ज, टी.एन.पी. एवं प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट कन्सेल्टेन्सी आदि के रूप में धनराशि अनुमन्य नही होगी। सेन्टेज/ पर्यवेक्षणीय चार्जेज देय नही होंगे। कन्टीजेन्सी के रूप में 2 प्रतिशत धनराशि देय होगी।

10- इरेक्शन चार्ज के रूप में सक्षम स्तर से अनुमोदित दरों पर धनराशि देय होगी और उस पर पृथक से अन्य कोई धनराशि देय नही होगी।

11- परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि आहरित कर बैंक / डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराई जायेगी।

12- प्रश्नगत धनराशि जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर प्रबन्ध निदेशक, मध्यान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को उपलब्ध कराई जायेगी।

13- स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2015 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2015 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2015 तक प्रमुख सचिव नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

14- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2015 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा ।

15- जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणात्मक कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा।

16- कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा । कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। इस संदर्भ में अधिकृत थर्ड पार्टी निरीक्षणकर्ता को भी अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा।

17- कार्य स्थल पर इसे त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ कार्य के मुख्य विवरण शिला पट्टिका / बोर्ड के रूप में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेंगे।

18- यथावश्यक द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के बाद वीडियोग्राफी भी करायी जाय।

19- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व जिलाधिकारी का होगा और उनके द्वारा तदनुसार नियोजन विभाग को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना प्रत्येक माह की 07 तारीख तक प्रेषित की जायेगी ।

20- कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्बंधित प्रशासकीय विभाग को किया जायेगा। प्रशासकीय विभाग द्वारा सृजित परिसम्पत्ति के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

http://sirsaidesh.up.nic.in

21- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

22- त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

23- ई.टी.एफ. द्वारा लिये गये निर्णय / निर्देशों का नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

24- नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

2- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40-आयोजनागत-लेखाशीर्षक-4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-05-संचरण एवं वितरण -800-अन्य व्यय -03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-01-विद्युत वितरण/ विद्युत केन्द्र/ विस्तार के लिए एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ई-5-410/दस-2015 दिनांक 29 मार्च,2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव

संख्या:167/2015/488(1)/35-4-2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3- प्रमुख सचिव / सचिव, ऊर्जा /लोक निर्माण / नगर विकास विभाग।
4- प्रमुख सचिव, वित्त।
5- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी ।
6- मण्डलायुक्त, देवीपाटन।
7- मुख्य विकास अधिकारी, बहराइच ।
8- प्रबन्ध निदेशक उ.प्र. पावर कारपोरेशन लिमिटेड लखनऊ।
9- प्रबन्ध निदेशक मध्यान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड।
10-वरिष्ठ कोषाधिकारी, बहराइच ।
11-गार्ड फाईल।
12-वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
13-राज्य योजना आयोग-1
14-जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, बहराइच ।

आज्ञा से,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in